

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) वधियक, 2023

प्रलिस के लयि:

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) वधियक, 2023, तटीय जलकृषि प्राधिकरण, [सी-वीड फार्मगि](#), [प्रदूषक भुगतान सदिधांत](#), [एंटीबायोडकिस](#)

मेन्स के लयि:

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) वधियक, 2023 से संबंघति प्रमुख प्रावधान

चर्चा में क्यो?

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) वधियक, 2023 को भारतीय संसद के दोनो सदनों द्वारा पारति कर दयिा गया है। इस संशोधन का लक्ष्य अस्पष्टताओं को दूर करना, प्रशासनिक प्रक्रयियों को सुव्यवस्थति करना और उभरती जलीय कृषि प्रथाओं को एकीकृत करना है।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण अधनियम, 2005:

- तटीय जलकृषि का आशय समुद्र तट अथवा मुहाने पर समुद्री अथवा खारे जलीय वातावरण में मछली, शंख और जलीय पादपों जैसे जलीय जीवों की खेती से है।
- इस अधनियम का उद्देश्य तट के करीब समुद्री भोजन की खेती में शामिल प्रक्रयियों की देख-रेख और वनियमन के लयितटीय जलकृषि प्राधिकरण नामक एक वशिष संगठन की स्थापना करना है।
- अधनियम के अनुसार, सरकार का कर्तव्य है कविह धारणीय तटीय जलकृषि की प्रथा सुनश्चिति करने के लयि आवश्यक कार्रवाई करे।

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) वधियक, 2023 से संबंघति प्रमुख प्रावधान:

- तटीय जलकृषि गतविधियों के दायरे में वृद्धि:
 - तटीय जलकृषि का वसितार: यह संशोधन वधियक इस अधनियम के दायरे में तटीय जलकृषि की सभी गतविधियों को व्यापक रूप से कवर करने के लयि व्यापक आधार वाली "तटीय जलकृषि" का प्रावधान करता है औस्तटीय जलकृषि के अन्य कार्य क्षेत्रों के बीच मूल अधनियम में मौजूद अस्पष्टता को दूर करता है।
 - उभरती जलकृषि प्रथाओं का समावेश: इस संशोधन के तहत झींगा पालन के साथ ही पर्यावरण के अनुकूल तटीय जलकृषि के नए रूपों जैसे- केज कल्चर, सी वीड कल्चर, बाई-वाल कल्चर, मरीन ऑर्नेमेंटल फिश कल्चर आदि को शामिल कयिा गया है।
 - इन गतविधियों में भारी राजस्व उत्पन्न करने और तटीय मछुआरा समुदायों, वशिष रूप से मछुआरा महिलाओं के लयि बड़े पैमाने पर रोजगार के अवसर पैदा करने की भी क्षमता है।
 - नो डेवलपमेंट जोन (NDZ) के भीतर जलकृषि इकाइयों को सुवधिा प्रदान करना: इस अधनियम के माध्यम से हैचरी, ब्रूडस्टॉक मल्टीपलकेशन सेंटर (BMC), और न्यूकलयिस बरीडगि सेंटर (NBC) जैसे प्रतष्ठितानों को अब हाई टाइड लाइन (HTL) से 200 मीटर के भीतर संचालति करने की अनुमति दे दी गई है।
 - संशोधन का उद्देश्य वर्ष 2005 के मूल CAA अधनियम की धारा 13(8) की व्याख्या द्वारा उत्पन्न पूर्व की अस्पष्टताओं को हल करना है, जसिमें तटीय जलीय कृषि को CRZ प्रतर्बिंधों से बाहर रखा गया था।
- वनियामक प्रक्रयियों को सरल बनाना एवं व्यावसायिक सुगमता को बढ़ावा देना:
 - पंजीकरण में संशोधन: मूल अधनियम में पंजीकरण के बनिा तटीय जलकृषि करने पर 3 वर्ष तक की कैद का प्रावधान है। यह पूरी तरह से नागरिक प्रकृति के अपराध के लयि बहुत कठोर सजा प्रतीत होती है और इसलयि इस संशोधन वधियक में प्रावधान कयिा गया है कनिागरिक अपराधों के गैर-अपराधीकरण के सदिधांत के अनुसार इस अपराध हेतु जुरमाने जैसी उपयुक्त नागरिक अनुकूल प्रणाली अपनाई जाएगी।
 - संचालनात्मक लचीलापन: संशोधन स्वामतिव या गतविधि के आकार में परविरतन के मामले में पंजीकरण प्रमाणपत्रों को संशोधति करने के

प्रावधान प्रस्तुत करते हैं।

- वे प्रशासनिक लचीलेपन में वृद्धि करते हुए तटीय जलकृषि प्राधिकरण को नवीनीकरण आवेदनों में देरी के लिये चक्रवृद्धि लागत वसूलने का अधिकार भी देते हैं।

■ पर्यावरण संरक्षण एवं अनुपालन:

- उत्सर्जन एवं अपशिष्टों के लिये मानक: संशोधन तटीय जलकृषि प्राधिकरण को जलीय कृषि इकाइयों से उत्सर्जन अथवा अपशिष्टों के लिये मानक स्थापित करने का अधिकार देता है, जिससे मालिकों को इन मानकों का पालन करने के लिये उत्तरदायी ठहराया जाता है।
 - प्रदूषक भुगतान संधि: यह संशोधन 'प्रदूषक भुगतान संधि' को बनाए रखता है, जिसके अंतर्गत जलीय कृषि इकाई मालिकों को प्राधिकरण द्वारा मूल्यांकन किये गए किसी भी पर्यावरण-संबंधी हानि या वधिवंस की लागत वहन करने के लिये बाध्य किया जाता है।
 - पारस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों में नषिध: संशोधन पारस्थितिक रूप से संवेदनशील क्षेत्रों अथवा महत्त्वपूर्ण भू-आकृति विज्ञान विशेषताओं वाले क्षेत्रों में तटीय जलीय कृषि गतिविधियों पर रोक लगाते हैं, जिससे कमज़ोर पारस्थितिक तंत्र की सुरक्षा बढ़ जाती है।
- बीमारियों की रोकथाम के प्रयास और धारणीय कृषि प्रथाओं का विकास:
- एंटीबायोटिक-मुक्त जलीय कृषि: एंटीबायोटिक दवाओं एवं औषधीय रूप से सक्रिय पदार्थों के उपयोग पर स्पष्ट रूप से प्रतिबंध लगाकर, संशोधन जलीय पारस्थितिकी प्रणालियों के स्वास्थ्य को प्राथमिकता देते हैं, साथ ही पर्यावरण के प्रति जागरूकता में वृद्धि भी करते हैं।

भारत में तटीय जलकृषि की स्थिति:

- भारत की तटरेखा लगभग 7,517 कि.मी. लंबी है और इसमें तटीय जलकृषि के विकास की व्यापक संभावनाएँ हैं। भारत में प्रमुख तटीय जलकृषि जीवों की प्रजातियाँ झींगा (Shrimp), मछली (Fish), केकड़ा (Crab), सीप (Oyster), मसलस (Mussel), सी-वीड (Seaweed) और मोती (Pearl) हैं।
 - पछिले 9 वर्षों में भारत में झींगा उत्पादन में 267% की वृद्धि हुई है।
- देश के समुद्री खाद्य नरियात में दोगुना प्रभाव देखा गया, जो वर्ष 2013-14 के 30,213 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2022-23 में 63,969 करोड़ रुपए हो गया।
 - वर्षीय रूप से इन नरियातों में बड़ा हिससा झींगा का है।
- आंध्र प्रदेश, गुजरात, ओडिशा और तमिलनाडु जैसे प्रमुख तटीय राज्यों ने तटीय जलकृषि झींगा उत्पादन और उसके बाद के नरियात के वसतिार को बढ़ावा देने में महत्त्वपूर्ण भूमिका निभाई।

नषिकर्ष:

तटीय जलकृषि प्राधिकरण (संशोधन) विधियक [Coastal Aquaculture Authority (Amendment) Bill], 2023 के नयिमों को स्पष्ट करके स्थायी प्रथाओं को बढ़ावा देने तथा पर्यावरण की सुरक्षा करके भारत के जलकृषि क्षेत्र को बढ़ाता है। यह SDG 14 (जल के नीचे जीवन/Life Below Water) के अनुरूप है और ज़मिमेदार आर्थिक विकास तथा पारस्थितिक कल्याण के लिये भारत की प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है।

UPSC सविलि सेवा परीक्षा, वगित वर्ष के प्रश्न

??????:

प्रश्न. भारत के नमिनलखिति क्षेत्रों में से किस एक में मैंग्रोव वन, सदापर्णी वन और पर्णपाती वनों का संयोजन है? (2015)

- उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश
- दक्षिण-पश्चिम बंगाल
- दक्षिणी सौराष्ट्र
- अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह

उत्तर: (d)

??????:

प्रश्न. 'नीली क्रांति' को परिभाषित करते हुए भारत में मत्स्यपालन की समस्याओं और रणनीतियों को समझाइये। (2018)

स्रोत: पी.आई.बी

